भारत में बेरोजगारी के मुद्दे

1. **भारत में बेरोजगारी से निपटने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इन नीतियों की संभावित सीमाओं पर चर्चा करें और व्यापक दृष्टिकोण के लिए अन्य उपाय सुझाएं।**

उत्तर:भारत में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई में राजकोषीय और मौद्रिक नीति शक्तिशाली उपकरण हो सकती हैं, लेकिन उनकी सीमाएँ हैं। यहां व्यापक दृष्टिकोण के लिए सुझावों के साथ एक विश्लेषण दिया गया है:

राजकोषीय नीति:

- **विस्तारवादी उपाय:**बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक कार्य कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा जाल पर बढ़ा हुआ सरकारी खर्च अल्पावधि में नौकरियां पैदा कर सकता है।
- **कर में कटौती:** व्यवसायों के लिए कर कम करने से निवेश और नियुक्तियों को प्रोत्साहन मिल सकता है। हालाँकि, इसके लिए राजस्व निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
- **लक्षित सब्सिडी:** उच्च बेरोजगारी का सामना कर रहे विशिष्ट क्षेत्रों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी लक्षित रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है।

सीमाएँ:

- **भीड़ हो रही है:** यदि सरकारी व्यय में वृद्धि से ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इससे निजी निवेश में कमी आ सकती है।
- **मुद्रा स्फ़ीति:** विस्तारवादी नीतियां मुद्रास्फीति को जन्म दे सकती हैं, खासकर यदि अर्थव्यवस्था पहले से ही पूरी क्षमता के करीब काम कर रही हो।
- **समय अंतराल:** राजकोषीय नीति उपायों को प्रभावी होने और रोजगार के स्तर को प्रभावित करने में समय लग सकता है।

मौद्रिक नीति:

- **कम ब्याज दरें:** केंद्रीय बैंक की ब्याज दर कम करने से उधार लेना सस्ता हो जाता है, व्यवसायों को निवेश करने और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में नई मुद्रा की शुरुआत:** परिसंपत्ति खरीद के माध्यम से धन आपूर्ति बढ़ाने से उधार लेने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है।

सीमाएँ:

- **परिसंपत्ति मूल्य बुलबुले:** कम ब्याज दरें परिसंपत्ति की कीमतें बढ़ा सकती हैं, जिससे संभावित रूप से वित्तीय अस्थिरता पैदा हो सकती है।
- **विनिमय दर प्रभाव:** कम ब्याज दरों से मुद्रा कमज़ोर हो सकती है, निर्यात पर असर पड़ सकता है और संभावित रूप से आयात की कीमतें बढ़ सकती हैं।
- **सीमित प्रभाव:** कौशल बेमेल के कारण होने वाली संरचनात्मक बेरोजगारी को संबोधित करने में मौद्रिक नीति उतनी प्रभावी नहीं हो सकती है।

व्यापक दृष्टिकोण:

बेरोजगारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक समाधानों के लिए संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने और मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता होती है। नीतियां इस प्रकार डिज़ाइन की जानी चाहिए:

- केवल सरकारी क्षेत्र ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दें।
- बेरोजगारी दर में क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करें।
- नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करें, अच्छे कार्य अवसर सुनिश्चित करें।
- कार्यबल में भाग लेने के लिए समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देना
- उद्यमिता संवर्धन
- कौशल विकास पहल

कौशल और उद्यमिता में लक्षित हस्तक्षेप और निवेश के साथ व्यापक आर्थिक उपकरणों को जोड़कर, भारत कम बेरोजगारी और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था वाले भविष्य की दिशा में प्रयास कर सकता है।

2. कल्पना कीजिए कि आप भारत सरकार के नीति सलाहकार हैं। भारतीय कार्यबल में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करें। नौकरी के नुकसान को कम करते हुए और श्रमिकों के लिए एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करते हुए इन प्रौद्योगिकियों की क्षमता का दोहन करने के लिए एक व्यापक रणनीति का प्रस्ताव करें।

उत्तर: भारतीय कार्यबल के लिए ऑटोमेशन और एआई की चुनौतियाँ और अवसर

चुनौतियाँ:

- **नौकरी में विस्थापन:** ऑटोमेशन और एआई द्वारा दोहराए जाने वाले और नियमित कार्यों की जगह लेने की संभावना है, जिससे विनिर्माण, डेटा प्रविष्टि और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में नौकरियां खत्म हो जाएंगी।
- **कौशल बेमेल:** नई एआई-संचालित नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल सेट वर्तमान में मांग से काफी भिन्न होंगे। इससे आवश्यक कौशल की कमी वाले लोगों के लिए कौशल अंतर और बेरोजगारी हो सकती है।
- **वेतन असमानता:** स्वचालन से एआई विकास और रखरखाव में अत्यधिक कुशल श्रमिकों को लाभ हो सकता है, जबकि कम-कुशल श्रमिकों को विस्थापित किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से आय असमानता बढ़ सकती है।
- **नैतिक प्रतिपूर्ति:** एआई एल्गोरिदम में पक्षपात भेदभावपूर्ण भर्ती प्रथाओं को जन्म दे सकता है और सामाजिक असमानताओं को कायम रख सकता है।

अवसर:

- **रोज़गार निर्माण:** AI विकास, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा और रोबोट रखरखाव जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियां पैदा करेगा।
- **बढ़ती हुई उत्पादक्ता:** स्वचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है, त्रुटियों को कम कर सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में समग्र उत्पादकता में सुधार कर सकता है।
- **कामकाजी परिस्थितियों में सुधार:** दोहराए जाने वाले और खतरनाक कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है, जिससे कार्यस्थल की सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण में सुधार होगा।
- **उन्नत नवाचार:** एआई नवाचार और वैज्ञानिक खोज को गति दे सकता है, जिससे नए उत्पाद, सेवाएं और आर्थिक विकास हो सकता है।

चुनौतियों को कम करने और अवसरों का दोहन करने के लिए व्यापक रणनीति:

1. कौशल विकास और पुनः कौशल:

- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम):** डेटा विज्ञान, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे एआई-विशिष्ट कौशल को शामिल करने के लिए एनएसडीएम कार्यक्रमों के दायरे का विस्तार करें।
- **उद्योग-अकादमिक सहयोग:** कौशल अंतर को पाटने के लिए अग्रणी तकनीकी कंपनियों के सहयोग से पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करें।
- **आजीवन सीखने की पहल:** मौजूदा श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, बूटकैंप और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर कौशल विकास को प्रोत्साहित करें।

2. श्रम बाजार सुधार और सामाजिक सुरक्षा जाल:

- **पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा लाभ:** पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा योजनाएं विकसित करें जो विशिष्ट नौकरियों से जुड़ी न हों, विस्थापित श्रमिकों के लिए निरंतर लाभ सुनिश्चित करें।
- **बेरोजगारी बीमा:** स्वचालन के कारण अपनी नौकरी खोने वाले श्रमिकों को अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बेरोजगारी बीमा योजनाएं शुरू करें।
- **श्रम कानूनों को अपनाना:** एआई के साथ उभर रही गिग इकॉनमी और प्लेटफ़ॉर्म-आधारित कार्य की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए श्रम कानूनों की समीक्षा करें और उन्हें अनुकूलित करें।

3. नवाचार और जिम्मेदार एआई विकास को बढ़ावा देना:

- **एआई अनुसंधान में निवेश:** मानव-केंद्रित एआई अनुप्रयोगों को विकसित करने और संभावित पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए एआई अनुसंधान में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाएं।
- **एआई के लिए नैतिक दिशानिर्देश:** निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एआई के विकास और तैनाती के लिए स्पष्ट नैतिक दिशानिर्देश स्थापित करें।
- **मानव-एआई सहयोग पर ध्यान दें:** ऐसी रणनीतियाँ विकसित करें जो पूर्ण प्रतिस्थापन के बजाय मानव-एआई सहयोग को बढ़ावा दें, इष्टतम परिणामों के लिए दोनों की ताकत का लाभ उठाएँ।

4. सार्वजनिक जागरूकता और सूचना साझा करना:

- **जन जागरूकता अभियान:** एआई और स्वचालन की क्षमता के बारे में जनता को शिक्षित करें, आजीवन सीखने और अनुकूलन क्षमता की संस्कृति को बढ़ावा दें।
- **श्रम बाज़ार सूचना प्रणाली:** उभरते नौकरी के अवसरों और कौशल आवश्यकताओं पर श्रमिकों को वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए व्यापक श्रम बाजार सूचना प्रणाली विकसित करें।
- **कैरियर परामर्श सेवाएँ:** कैरियर परामर्श सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करें जो व्यक्तियों को एआई-प्रासंगिक कैरियर पथों की ओर मार्गदर्शन कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

ऑटोमेशन और एआई भारतीय कार्यबल को बदल रहे हैं। सक्रिय रूप से चुनौतियों का समाधान करके और अवसरों का लाभ उठाकर, भारत स्थायी आर्थिक विकास हासिल करने, श्रमिकों की भलाई में सुधार करने और एआई के युग में अपने कार्यबल के लिए एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा सकता है। कौशल विकास,

सामाजिक सुरक्षा जाल, एआई के नैतिक विकास और सार्वजनिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने वाली यह व्यापक रणनीति भारत में काम के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

3. "बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी अस्वस्थता का एक लक्षण है।" इस कथन पर चर्चा करें. भारत में बेरोजगारी में योगदान देने वाले संरचनात्मक कारकों का विश्लेषण करें और एक बहु-आयामी दृष्टिकोण का सुझाव दें जो इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करता हो।

उत्तर: **बेरोज़गारी: भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी अस्वस्थता का एक लक्षण**
यह कथन कि "बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी अस्वस्थता का एक लक्षण है" सत्य है। जबकि उच्च बेरोजगारी दर अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय है, वे अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दों की ओर इशारा करते हैं जो कुशल रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं।

बेरोजगारी में योगदान देने वाले संरचनात्मक कारक:

- **कौशल बेमेल:** शिक्षा प्रणाली अक्सर स्नातकों को नौकरी बाजार द्वारा मांग की जाने वाली उद्योग-प्रासंगिक कौशल से लैस करने में विफल रहती है। इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां स्नातकों के पास नियोक्ता द्वारा मांगे जाने वाले विशिष्ट कौशल की कमी होती है, जिससे कौशल में अंतर पैदा होता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** भारतीय कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसकी विशेषता कम वेतन, अनौपचारिकता और सामाजिक सुरक्षा की कमी है। हालाँकि यह रोजगार प्रदान करता है, लेकिन यह उत्पादकता वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है या आर्थिक विकास के लिए एक स्थायी आधार तैयार नहीं करता है।
- **प्रमुख क्षेत्रों में धीमी गति से रोजगार सृजन:** कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से विनिर्माण, कार्यबल में नए प्रवेशकों को शामिल करने के लिए पर्याप्त तेजी से विस्तार नहीं कर रहे हैं। यह सीमित बुनियादी ढांचे, उच्च इनपुट लागत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे कारकों के कारण है।
- **जनसांख्यिकी उभार:** भारत की युवा आबादी एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, लेकिन यह रोजगार सृजन पर लगातार दबाव भी डालती है। नौकरी चाहने वालों की बढ़ती संख्या के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से बढ़ने की जरूरत है।
- **कठोर श्रम कानून:** कुछ लोगों का तर्क है कि कड़े श्रम नियम व्यवसायों को नए कर्मचारियों को काम पर रखने से हतोत्साहित कर सकते हैं, विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में, अनम्य भर्ती और बर्खास्तगी प्रथाओं के बारे में चिंताओं के कारण।

अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना: एक बहुआयामी दृष्टिकोण

- **शिक्षा प्रणाली सुधार:** मुख्य विषयों के साथ-साथ आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और व्यावहारिक कौशल पर जोर देने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करें। कौशल अंतर को पाटने के लिए उद्योग की जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें।
- **औपचारिकता को बढ़ावा देना:** ऐसी नीतियां लागू करें जो अनौपचारिक क्षेत्र में व्यवसायों को अपने संचालन को औपचारिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अधिक पारदर्शी और विनियमित रोजगार वातावरण तैयार हो सकता है, अधिक निवेश आकर्षित हो सकता है और सतत विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** कनेक्टिविटी में सुधार, व्यावसायिक लागत कम करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सड़क, बिजली और लॉजिस्टिक्स जैसी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में निवेश करें।
- **विनिर्माण और एमएसएमई को बढ़ावा देना:** ऐसी नीतियां लागू करें जो श्रम-केंद्रित विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करें और ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक आसान पहुंच के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का समर्थन करें। इससे अधिक विविधतापूर्ण और रोजगार-संपन्न औद्योगिक आधार तैयार किया जा सकता है।
- **श्रम बाज़ार सुधार:** उन सुधारों पर विचार करें जो व्यवसाय विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ श्रमिकों के अधिकारों को संतुलित करते हैं। इसमें नियमों को सुव्यवस्थित करना और लचीली कार्य व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

बेरोज़गारी महज़ एक अकेली समस्या नहीं है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी अस्वस्थता का लक्षण है। बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से संरचनात्मक कारकों को संबोधित करके, भारत एक अधिक कुशल नौकरी बाजार बना सकता है, समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है और अपने युवा कार्यबल की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है। इसके लिए अधिक मजबूत और गतिशील आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायों और नागरिक समाज के सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है जो रोजगार सृजन और साझा समृद्धि को बढ़ावा दे।

4. भारत में गिग इकॉनमी एक बढ़ती हुई घटना है, जो अवसर और चुनौतियाँ दोनों पेश करती है। पारंपरिक रोजगार पैटर्न पर गिग अर्थव्यवस्था के प्रभाव पर चर्चा करें और गिग श्रमिकों के लिए उचित व्यवहार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएं।

उत्तर: **द गिग इकोनॉमी: भारत में कार्य को नया आकार देना**

अल्पकालिक, अनुबंध-आधारित काम की विशेषता वाली गिग अर्थव्यवस्था, भारतीय कार्यबल परिदृश्य को तेजी से बदल रही है। यह अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है, पारंपरिक रोजगार पैटर्न को बाधित करता है और श्रमिकों की भलाई के बारे में चिंताएँ बढ़ाता है।

पारंपरिक रोज़गार पर प्रभाव:

- **लचीलापन और कार्य-जीवन संतुलन:** गिग इकॉनमी श्रमिकों के लिए लचीलापन प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपने काम के घंटे और परियोजनाएं चुनने की अनुमति मिलती है, जिससे संभावित रूप से कार्य-जीवन संतुलन में सुधार होता है।
- **आय सृजन के अवसर:** यह विविध कौशल सेट वाले व्यक्तियों के लिए आय के नए रास्ते बनाता है, विशेष रूप से अतिरिक्त आय चाहने वाले या उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने वाले लोगों के लिए।
- **व्यापक प्रतिभा पूल तक पहुंच:** व्यवसाय व्यापक प्रतिभा पूल तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जिससे वे परियोजना की जरूरतों के आधार पर अपने कार्यबल को ऊपर या नीचे करने में सक्षम होते हैं।
- **नौकरी की सुरक्षा का क्षरण:** स्थिर आय और लाभ वाली पारंपरिक पूर्णकालिक नौकरियाँ घट रही हैं। गिग श्रमिकों को आय के बारे में अनिश्चितता और नौकरी की सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है।

- **शोषण और अनुचित आचरण:** गिग अर्थव्यवस्था कम वेतन, स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभों की कमी और अनुचित श्रम प्रथाओं के साथ प्लेटफार्मों द्वारा शोषण का कारण बन सकती है।

उचित व्यवहार और सामाजिक सुरक्षा के उपाय:

- **गिग प्लेटफार्मों का विनियमन:**गिग श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, उचित कामकाजी परिस्थितियों और विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नियमों की आवश्यकता है।
- **पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा लाभ:** पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा योजनाएं विकसित करें जो गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और पेंशन में योगदान करने में सक्षम बनाती हैं, चाहे वे किसी भी मंच पर काम करते हों।
- **कौशल विकास कार्यक्रम:** गिग श्रमिकों के कौशल और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए गिग अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करें।
- **श्रमिक संघों को बढ़ावा देना:** बेहतर वेतन और कामकाजी परिस्थितियों के लिए सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने के लिए गिग श्रमिकों के लिए श्रमिक संघों के गठन की सुविधा प्रदान करना।
- **डेटा साझाकरण और पारदर्शिता:** प्लेटफ़ॉर्म को डेटा साझाकरण प्रथाओं और एल्गोरिदम में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए जो श्रमिकों की आय और अवसरों को प्रभावित करते हैं।

आशा करना:

गिग इकॉनमी कई भारतीयों के लिए काम के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। इन उपायों को लागू करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि गिग अर्थव्यवस्था से श्रमिकों और व्यवसायों दोनों को लाभ हो। श्रमिकों के लिए उचित व्यवहार और सामाजिक सुरक्षा के साथ एक अच्छी तरह से विनियमित गिग अर्थव्यवस्था अधिक समावेशी और गतिशील भारतीय कार्यबल में योगदान कर सकती है।

अतिरिक्त मुद्दो पर विचार करना:

- समान अवसर सुनिश्चित करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान देने के लिए गिग अर्थव्यवस्था में कराधान की संभावित भूमिका का पता लगाएं।
- विश्लेषण करें कि कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाने और अधिक सुरक्षित गिग इकॉनमी वातावरण बनाने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।
- राइड-हेलिंग और डिलीवरी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में श्रमिक सुरक्षा और उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा करें।

इन पहलुओं पर विचार करके, आप भारत में विकसित हो रही गिग अर्थव्यवस्था और काम के भविष्य पर इसके प्रभाव की अधिक व्यापक समझ विकसित कर सकते हैं।